

प्रेषक,

आर०सी० लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून दिनांक: १३ अक्टूबर, २००९

विषय: केन्द्र पोषित बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के
सितारगंज एवं चोरगलिया तथा जनपद नैनीताल की बाढ़ सुरक्षा योजनाओं
की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियन्त्रण
आयोग के पत्रसंख्या GFCC/MP-II/203/2009/5579 दिनांक 25-08-2009, पत्रसंख्या
GFCC/MP-II/155/2009/5569-72 दिनांक 24-08-2009 एवं GFCC/MP-II/156/2009/
5559-62 दिनांक 24-08-2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री
राज्यपाल निम्न विवरणानुसार केन्द्र पोषित योजनाओं में निम्न तालिका के अनुसार
रु० 1423.8720 लाख तथा रु० 1231.39 लाख कुल रु० 2655.2620 लाख (रु०
छब्बीस करोड़ पचपन लाख छबीस हजार दो सौ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक
स्वीकृति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल लागत	टी०ए०सी० वित्त द्वारा परीक्षित	जी.एफ.सी.सी. भारत सरकार द्वारा संस्तुत	स्वीकृति का प्रकार
1	2	3	4	5	6
1	जनपद नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के चोरगलिया क्षेत्र एवं सितारगंज क्षेत्र में नन्धौर व उसकी सहायक नदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना।	1811.31	1797.17	1423.8720	प्रशासनिक स्वीकृति
2	जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर में कोसी एवं उसकी सहायक नदियों से ग्राम खैरना, चुकुम, मोहान, रामनगर शहर, वैतखेडी, नस्तनगर अजतपुर, गोवरा व जोगीपुरा की बाढ़ सुरक्षा योजना	714.63	727.01	726.00	वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति
3	जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर में ढैला नदी से ग्राम सेमखलिया, ढैला ग्राम टी०वी०पीडर, लक्ष्मीपुर पट्टी, बेलजुडी, बासखेड़ा, रायपुर एवं जगन्नाथपुर की सुरक्षा योजना	555.33	552.74	505.39	वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति
	कुल योग	3141.27	3076.92	2655.262	

2- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :-

1. योजनाओं का क्रियान्वयन/कार्य प्रारम्भ तभी किया जायेगा जब केन्द्रांश स्वीकृत होकर प्रथम किस्त प्राप्त हो जायेगी।
2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरों शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
3. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी लागत स्वीकृत की गयी है ।
5. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए ।
6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें ।
7. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन कड़ाई से किया जाए ।
8. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए ।
9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य कर लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए ।
10. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें ।

यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-543/XXVII(2)/2009 दिनांक 06.10.09 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव

संख्या 3600 / 11-2008-04(08)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सज्ञानार्थ ।
3. सदस्य(सी), भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, सिंचाई भवन, तीसरी मंजिल, पटना को उनके उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में ।
4. वित्त अनुभाग-2 ।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर ।
6. नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड ।
9. गार्ड फाईल ।

अज्ञा सी,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव